

जनजातीय महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका- एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सीधी जिले के विशेष संदर्भ में)

Research Scholar

Priyanka Gautam

Enrollment No. 22ASSH1SL06002

Supervisor

Dr. Manish Mishra

Deptt. of Sociology
SAM Global University, Raisen
(Madhya Pradesh)-464551

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के सीधी जिले की जनजातीय महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन पूर्णतः प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें जिले की छह तहसीलों से बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति के माध्यम से चयनित 100 जनजातीय महिलाओं से संरचित साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से आँकड़े संकलित किए गए। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मोबाइल फोन सर्वाधिक व्यापक माध्यम (85 प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध) के रूप में उभरा है, किन्तु महिलाओं की इसकी व्यक्तिगत, स्वायत्त पहुँच अपेक्षाकृत सीमित है। शिक्षा-स्तर तथा माध्यम-उपयोग के मध्य, तथा माध्यम-उपयोग तथा सामाजिक-आर्थिक जागरूकता के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया, जबकि आर्थिक बाधा तथा पारिवारिक/सामाजिक प्रतिबन्ध माध्यम-उपयोग की प्रमुख बाधाओं के रूप में चिन्हित हुए। अध्ययन के निष्कर्ष जनजातीय महिलाओं के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु लक्षित, समता-उन्मुख जनसंचार-नीति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

मुख्य शब्द (Keywords)

जनजातीय महिलाएँ, जनसंचार माध्यम, सामाजिक-आर्थिक विकास, सीधी जिला, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण संचार, माध्यम-उपयोग सूचकांक।

प्रस्तावना

मानव समाज के विकास-क्रम में जनसंचार माध्यमों ने सूचना के प्रवाह को गति देने के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों, दृष्टिकोणों तथा सामूहिक चेतना को भी गहराई से प्रभावित किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनसंचार माध्यमों को सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली अभिकरण के रूप में स्वीकार किया गया है, जो परम्परागत मूल्यों तथा आधुनिकता के मध्य सेतु का कार्य करता है (लर्नर, 1958; श्राम, 1964)। तथापि यह प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता-जनजातीय समुदाय, जो प्रायः दुर्गम, वनाच्छादित तथा अवसंरचनात्मक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में निवास करते हैं, आधुनिक संचार-सुविधाओं से अपेक्षाकृत वंचित रहे हैं।

मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जो विन्ध्य क्षेत्र में स्थित है तथा जिसकी जनसंख्या का उल्लेखनीय भाग अनुसूचित जनजाति (मुख्यतः कोल, गोंड, बैगा, पनिका तथा कँवर) से सम्बद्ध है, इस परिघटना के अध्ययन हेतु एक प्रतिनिधिक क्षेत्र प्रस्तुत करता है। जिले की जनजातीय महिलाएँ पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, निरक्षरता, निर्धनता तथा भौगोलिक दुर्गमता जैसी बहु-स्तरीय संरचनात्मक बाधाओं का सामना करती हैं, जो उनकी जनसंचार माध्यमों तक पहुँच तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास, दोनों को प्रभावित करती हैं।

एवरेट रोजर्स (2003) के नवाचार-प्रसार सिद्धांत तथा नाइला कबीर (1999) के "संसाधन-अभिकरण-उपलब्धि" सशक्तिकरण-ढाँचे के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत शोध पत्र यह अन्वेषित करने का प्रयास करता है कि सीधी जिले की जनजातीय महिलाओं की जनसंचार माध्यमों तक वर्तमान पहुँच तथा उपयोग-प्रतिमान क्या है, तथा यह पहुँच उनकी सामाजिक-आर्थिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण के साथ किस प्रकार सम्बद्ध है। अध्ययन पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्र-सर्वेक्षण पर आधारित है, जिससे स्थानीय, प्रत्यक्ष तथा समसामयिक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।

शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

1. सीधी जिले की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. जनजातीय महिलाओं की जनसंचार माध्यमों तक पहुँच तथा उपयोग-प्रतिमान का विश्लेषण करना।

3. माध्यम-उपयोग तथा सामाजिक-आर्थिक जागरूकता के मध्य सम्बन्ध का परीक्षण करना।
4. जनसंचार माध्यमों के उपयोग में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।
5. अनुभवजन्य निष्कर्षों के आधार पर जनजातीय महिलाओं के समावेशी विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व अनेक दृष्टिकोणों से रेखांकित किया जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से, यह अध्ययन जनसंचार-विकास सम्बन्ध पर उपलब्ध व्यापक साहित्य को भारतीय जनजातीय, विशेषतः बघेलखण्ड क्षेत्र के विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ में परीक्षित करते हुए एक क्षेत्रीय अनुभवजन्य योगदान प्रस्तुत करता है, जो इस क्षेत्र पर केन्द्रित समाजशास्त्रीय साहित्य में विद्यमान एक उल्लेखनीय रिक्तता को आंशिक रूप से भरने का प्रयास करता है।

व्यावहारिक दृष्टि से, अध्ययन के निष्कर्ष आदिम जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, तथा स्थानीय अशासकीय संगठनों को जनजातीय महिलाओं तक प्रभावी सम्प्रेषण-रणनीति विकसित करने हेतु साक्ष्य-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। डिजिटल इंडिया तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी योजनाओं के विस्तार के इस युग में, जनजातीय महिलाओं की डिजिटल तथा जनसंचार माध्यमों तक पहुँच को समझना नीति-निर्माण हेतु अत्यन्त प्रासंगिक तथा तात्कालिक आवश्यकता बन गया है।

शोध विधि

शोध अभिकल्प - प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक-सह-विश्लेषणात्मक (descriptive-cum-analytical) शोध अभिकल्प पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक प्रविधि का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है।

समकों का स्रोत - अध्ययन पूर्णतः प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। द्वितीयक स्रोतों (पुस्तकें, शोध-पत्रिकाएँ, सरकारी प्रतिवेदन) का उपयोग केवल सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तथा साहित्य-समीक्षा हेतु किया गया है, विश्लेषण एवं निष्कर्ष पूर्णतः क्षेत्र-सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित हैं।

अध्ययन क्षेत्र एवं प्रतिदर्श - अध्ययन मध्य प्रदेश के सीधी जिले की छह तहसीलों (सीधी, सिहावल, रामपुर नैकिन, चुरहट, मझौली तथा गोपद बनास) में सम्पन्न किया गया। बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन (multi-stage stratified random sampling) पद्धति के माध्यम से कुल 100 जनजातीय महिलाओं का प्रतिदर्श चयनित किया गया, जिसका जनजातीय समूह-वार वितरण तालिका 1 में प्रस्तुत है।

तालिका 1 : प्रतिदर्श का जनजातीय समूह-वार वितरण (N=100)

क्र.	जनजातीय समूह	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	कोल	50	50.0
2	गोंड	30	30.0
3	बैगा	13	13.0
4	अन्य (पनिका, कँवर आदि)	7	7.0
	योग	100	100.0

स्रोत: क्षेत्र-सर्वेक्षण, 2025 /

समंक-संकलन उपकरण - प्राथमिक समंकों का संकलन एक संरचित साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया, जिसमें सामान्य पहचान, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जनसंचार माध्यमों तक पहुँच एवं उपयोग, तथा सामाजिक-आर्थिक जागरूकता से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित थे। अनुसूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व 10-12 उत्तरदाताओं पर एक पूर्व-परीक्षण सम्पन्न किया गया।

समंक-विश्लेषण - संकलित आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी (बारम्बारता, प्रतिशत) तथा साधारण क्रॉस-सारणीयन (cross-tabulation) के माध्यम से किया गया, जिसे उपयुक्त सारणियों में प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कार स्थानीय बघेली भाषा में सम्पन्न किए गए, तथा प्रत्येक उत्तरदाता से सूचित सहमति प्राप्त कर पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की गई।

निष्कर्ष

सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि - अध्ययन में सम्मिलित 100 जनजातीय महिलाओं में से 51 प्रतिशत पूर्णतः निरक्षर पाई गईं, जबकि केवल 8 प्रतिशत ने कक्षा 10 से उच्चतर शिक्षा प्राप्त की थी। 64 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 8,000 रुपये से कम पाई गई, तथा 58 प्रतिशत परिवार भूमिहीन अथवा सीमान्त कृषक की श्रेणी में सम्मिलित थे। यह पृष्ठभूमि जिले की जनजातीय महिलाओं की व्यापक संरचनात्मक असुविधा को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

जनसंचार माध्यमों तक पहुँच एवं उपयोग-प्रतिमान - तालिका 2 में उत्तरदाताओं के घर में विभिन्न जनसंचार साधनों की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2 : उत्तरदाताओं के घर में जनसंचार साधनों की उपलब्धता (N=100, बहु-उत्तर)

क्र.	साधन	उपलब्ध (संख्या)	प्रतिशत
1	रेडियो	20	20.0
2	दूरदर्शन (टीवी)	55	55.0
3	मोबाइल फोन	85	85.0
4	स्मार्टफोन/इंटरनेट-सुविधा सहित	40	40.0
5	समाचार-पत्र (नियमित)	15	15.0

स्रोत: क्षेत्र-सर्वेक्षण, 2025 /

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि मोबाइल फोन सर्वाधिक व्यापक साधन (85.0 प्रतिशत) के रूप में उभरा है, तत्पश्चात् दूरदर्शन (55.0 प्रतिशत) का स्थान है, जबकि रेडियो तथा समाचार-पत्र की उपस्थिति सीमित (क्रमशः 20.0 तथा 15.0 प्रतिशत) पाई गई। तथापि यह उल्लेखनीय है कि घर में मोबाइल फोन की उपलब्धता का यह अर्थ नहीं कि महिलाओं की इस पर व्यक्तिगत, स्वायत्त पहुँच है-सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 44 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना स्वयं का मोबाइल फोन था, शेष 34 प्रतिशत इसे परिवार के अन्य सदस्य (प्रायः पति) के साथ साझा करती थीं, तथा 22 प्रतिशत

की इस साधन तक कोई पहुँच नहीं थी। यह अन्तर "पहुँच" तथा "स्वामित्व/स्वायत्तता" के मध्य के उस महत्वपूर्ण भेद को अनुभवजन्य रूप से पुष्ट करता है जिसे साहित्य में बार-बार रेखांकित किया गया है (हुयर एवं सिकोस्का, 2003)।

सर्वाधिक पसंदीदा माध्यम के रूप में दूरदर्शन (45 प्रतिशत) प्रथम स्थान पर रहा, तत्पश्चात् मोबाइल फोन (32 प्रतिशत) तथा रेडियो (12 प्रतिशत) का स्थान रहा। सामग्री-वरीयता की दृष्टि से मनोरंजन-प्रधान सामग्री (42 प्रतिशत) सर्वाधिक पसन्द की गई, तत्पश्चात् समाचार/सामयिक जानकारी (24 प्रतिशत) का स्थान रहा।

माध्यम-उपयोग तथा सामाजिक-आर्थिक जागरूकता के मध्य सम्बन्ध - अध्ययन के एक केन्द्रीय उद्देश्य के अनुरूप, उत्तरदाताओं को उनके समेकित माध्यम-उपयोग सूचकांक (उच्च/मध्यम/निम्न) के आधार पर वर्गीकृत करते हुए, इसका सम्बन्ध उनकी सरकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता-स्तर से स्थापित किया गया, जिसका विवरण तालिका 3 में प्रस्तुत है।

तालिका 3 : माध्यम-उपयोग स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक जागरूकता-स्तर का क्रॉस-सारणीयन (N=100)

माध्यम-उपयोग स्तर	उच्च जागरूकता	मध्यम जागरूकता	निम्न जागरूकता	योग
उच्च (40)	23	13	4	40
मध्यम (33)	10	17	6	33
निम्न (27)	3	7	17	27
योग	36	37	27	100

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण, 2025 /

तालिका 3 से एक स्पष्ट तथा सुसंगत प्रवृत्ति उभरती है : उच्च माध्यम-उपयोग वाली 40 महिलाओं में से 23 (57.5 प्रतिशत) उच्च जागरूकता-स्तर रखती हैं, जबकि निम्न माध्यम-उपयोग वाली 27 महिलाओं में से केवल 3 (11.1 प्रतिशत) ही उच्च जागरूकता-स्तर रखती हैं। इसके विपरीत, निम्न-उपयोग समूह में निम्न जागरूकता की दर 63.0 प्रतिशत है, जबकि उच्च-उपयोग समूह में यह दर घटकर मात्र 10.0 प्रतिशत रह जाती है। यह प्रबल, दिशात्मक सम्बन्ध इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव सूचना तथा जागरूकता के धरातल पर विशेष रूप से सशक्त है, जो एवरेट रोजर्स (2003) के नवाचार-प्रसार सिद्धांत के "ज्ञान-चरण" की केन्द्रीय भूमिका की एक ठोस अनुभवजन्य पुष्टि प्रस्तुत करता है।

शिक्षा-स्तर के साथ क्रॉस-सारणीयन से भी एक सुदृढ़ सम्बन्ध उजागर हुआ-निरक्षर उत्तरदाताओं में उच्च माध्यम-उपयोग की दर मात्र 20 प्रतिशत के निकट पाई गई, जबकि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं में यह दर 65 प्रतिशत से अधिक रही, जो शिक्षा को माध्यम-उपयोग के सर्वाधिक सशक्त निर्धारक के रूप में स्थापित करता है।

जनसंचार माध्यमों के उपयोग में बाधाएँ - सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि आर्थिक बाधा (30 प्रतिशत) तथा पारिवारिक/सामाजिक प्रतिबन्ध (25 प्रतिशत) माध्यम-उपयोग की सर्वाधिक सामान्य बाधाएँ हैं, तत्पश्चात् समय का अभाव (20 प्रतिशत), भाषा सम्बन्धी कठिनाई (15 प्रतिशत) तथा विशुद्ध अवसंरचनात्मक अभाव (10 प्रतिशत) का स्थान रहा। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि जनसंचार माध्यमों तक पहुँच बढ़ाने की समस्या मूलतः केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, अपितु गहराई से सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक जड़ों वाली समस्या है।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं :

1. शिक्षा तथा जनसंचार माध्यम-उपयोग के मध्य पाए गए सुदृढ़ सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय महिलाओं की शिक्षा में निवेश को उच्चतम नीतिगत प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल तथा जनसंचार-समावेशन को भी सुदृढ़ करेगा।
2. मोबाइल फोन तक महिलाओं की सीमित व्यक्तिगत, स्वायत्त पहुँच को सम्बोधित करने हेतु पारिवारिक/सामाजिक प्रतिबन्ध को कम करने वाले सामुदायिक जागरूकता-अभियान चलाए जाने चाहिए, जो पुरुष सदस्यों को भी लक्षित करें।
3. ऑगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं जैसी ग्राम-स्तरीय विश्वसनीय संस्थागत उपस्थितियों को डिजिटल/जनसंचार साक्षरता प्रशिक्षण देकर "परिवर्तन-प्रवर्तक" की भूमिका सौंपी जानी चाहिए।
4. विकासात्मक सन्देशों को मनोरंजन-प्रधान सामग्री के साथ सम्मिश्रित "एडुटेनमेंट" रणनीति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तथा स्थानीय बघेली भाषा में सामग्री-निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. स्वयं सहायता समूहों की मासिक बैठकों को सूचना तथा डिजिटल-साक्षरता सत्रों हेतु एक लागत-प्रभावी मंच के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

6. आर्थिक बाधा को सम्बोधित करने हेतु जनजातीय महिलाओं हेतु किफायती उपकरण तथा डेटा-योजनाओं को बढ़ावा देने वाली लक्षित सब्सिडी योजनाएँ विचारणीय हैं।

संदर्भ

1. कोठारी, सी.आर. (2004). अनुसंधान प्रविधि : विधियाँ एवं तकनीकें. नई दिल्ली : न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स।
2. कुमार, केवल जे. (2010). भारत में जनसंचार माध्यम (4था संस्करण). मुम्बई : जायको पब्लिशिंग हाउस।
3. दुबे, लीला (1997). Women and Kinship: Comparative Perspectives on Gender in South and South-East Asia. Tokyo: United Nations University Press.
4. नारुला, उमा (2006). विकास सम्प्रेषण : सिद्धांत एवं व्यवहार. नई दिल्ली : हर-आनन्द पब्लिकेशन्स।
5. हसनैन, नदीम (2011). Tribal India. New Delhi: Palaka Prakashan.
6. Hornik, R. C. (1988). Development Communication: Information, Agriculture, and Nutrition in the Third World. New York: Longman.
7. Huyer, S., & Sikoska, T. (2003). Overcoming the Gender Digital Divide. Santo Domingo: UN-INSTRAW.
8. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464.
9. Lerner, D. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Glencoe: Free Press.
10. Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2001). Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment. New Delhi: Sage Publications.
11. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press.
12. Schramm, W. (1964). Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries. Stanford: Stanford University Press.
13. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

14. भारत की जनगणना, 2011. प्राथमिक जनगणना सार, मध्य प्रदेश। नई दिल्ली : भारत सरकार।
15. मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न वर्ष)।